बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company
बिहार सरकार का एक उपक्रम
वेबसाइट: www.bsbccl.bih.nic.in

BSBCCL
Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company
A Government of Bihar Undertaking
Website: www.bsbccl.bih.nic.in

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0–42/2015–परामर्शी सेवा 18(313) दिनांक : 08/01/18

प्रेषक,

रमेश कुमार
मुख्य महाप्रबंधक।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
बिहार, पटना।

विषय : माह दिसम्बर, 2017 तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।

प्रसंगः–निगम का पत्रांक–2969(अनु0) दिनांक–25.09.2017.

महाशय,

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से 36 जिला मुख्यालयों में प्रेस क्लब भवनों के निर्माण कार्य की योजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई थी। पत्रांक–185, दिनांक–17.03.2015 द्वारा ₹77.12 लाख प्रति अदद की दर से 36 प्रेस क्लबो के निर्माण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹27.7632 करोड़ है। माह अगस्त, 2017 की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से भेजा जा चुका है।

निगम स्तर पर माह दिसम्बर, 2017 तक की अद्यतन समीक्षा के आधार पर समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

2. <u>भौतिक प्रगति</u>

36 प्रेस क्लबों में से 32 कार्य स्थलों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 01 स्थलों पर कार्य प्रगति पर है। जमुई का मामला पटना उच्च न्यायालय में है। सिवान का कार्य प्रगति पर है। गया में कार्य बाधित है।

2.2 <u>वित्तीय प्रगति</u>

36 प्रेस क्लबों के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹27.7632 करोड़ है जिसके विरुद्ध अब तक ₹27.7632 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त आवंटित राशि से अब तक कुल ₹21.49 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। योजनावार अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन संलग्न है।

2.3 <u>विभाग से निधि की उपलब्धता</u>

36 प्रेस क्लबों के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹27.7632 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹27.7632 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। अतः निधि की आवश्यकता नहीं है।

2.4 <u>निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण</u>

31 मार्च 2016 तक के व्यय का ₹5.69 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र पत्रांक–880 दिनांक–20.04.2016 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।

2.5 <u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन</u>

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को 11.00 बजे पूर्वाह्न निगम मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित होता है। बैठक में भाग लेने हेतु एक नोडल पदाधिकारी को भेजने की कृपा की जाये ताकि कार्य प्रगति एवं समस्याओं का बेहतर अनुश्रवण हो एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके।

2.6 <u>ध्यानाकर्षण हेतु प्रमुख मुद्दे</u>

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा सभी कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए ऑन लाईन प्रोजेक्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम लागू किया गया है। योजनाओं की अद्यतन जानकारी निगम के वेबसाईट www.bsbccl.bih.nic.in पर मौजुद ऑन लाईन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम लिंक द्वारा ली जा सकती है। इसके लिए यूजर आई डी एवं पासवर्ड निगम के पत्रांक–1186 दिनांक–20.05.2016 द्वारा अवर सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को भेजा जा चुका है।

3. <u>अनुरोध</u>

अनुरोध है कि विभागीय स्तर से भी कार्यों की समीक्षा/अनुश्रवण कराने की कृपा की जाये एवं इस पर अगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाये । जिन कार्यस्थलों के लिये निर्विवादित तरीके से जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उनपर सुविचारित निर्णय लेकर उनकी प्रशासनिक स्वीकृति रद्द की जाये।
अनु0:—यथोक्त।

विश्वासभाजन

(रमेश कुमार)

ज्ञापांक:— 18 दिनांक— 08/01/2018
प्रतिलिपि :सभी महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, आई0टी0 मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा)

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

विभाग का नाम : सूचना एवं जन–संपर्क विभाग

दिनांक : 10.12.2017

कम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि (सेंटेज सहित)	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिहार राज्य के 36 जिला मुख्यालय में प्रेस क्लब भवन का निर्माण कार्य।	₹ 27.7632 करोड़ (₹ 77.12 लाख प्रति अद्द) पत्रांक–185, दिनांक–17.03.2015 पत्रांक–699, दिनांक–14.01.2016	₹ 27.7632 करोड़ (वर्ष 2015–16 में)	₹ 21.49 करोड़	* कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित : 25 * कार्य पूर्ण : 07 (सारण, किशनगंज, लखीसराय, रोहतास, औरंगाबाद, बाँका एवं हाजीपुर) * विभिन्न चरणो में कार्य प्रगति पर : 01 (जहानाबाद) * **सीवान** : कार्य प्रारंभ होने की प्रकिया में। * समस्याग्रस्त : 02 गया : नीव कार्य कराया जा रहा था। SBI, गया के प्रबंधक द्वारा कार्य रोक दिया गया है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उक्त भूखण्ड का उपयोग साईकिल स्टैड के रूप में किया जा रहा है। इस संबंध में डी0पी0आर0ओ0, गया को पी0आई0यू0, गया के पत्रांक–732, दिनांक–23.11.2017 द्वारा अवगत कराया गया है। जमुई : *पूर्व में कार्य आवंटित किया गया था परंतु संवेदक द्वारा एकरारनामा नहीं किया जा रहा था। अक्टुबर 2016 में स्थल उपलब्धता के उपरांत भी उनके द्वारा कार्य नहीं शुरु किये जाने पर उक्त निविदा रद्द कर दी गई तथा पुर्ननिविदा आमंत्रित कर दी गई जिसमें 2 निविदा प्राप्त हुई है। पूर्व के संवेदक द्वारा इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC दायर कर दिया गया है। निर्णयोपरांत हीं निविदा का निष्पादन किया जा सकेगा।* *प्रशासी विभाग से पूर्ण योजनाओं का हस्तांतरण लिये जाने का आग्रह है।*	दिसंबर 2017	* निगम के पत्रांक–880, दिनांकः 20.04.2016 द्वारा दिनांक–31.03.2016 तक के व्यय के लिए ₹ 5.69 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को भेजा गया। * निगम के पत्रांक–2969, दिनांकः 25.09.2017 द्वारा अगस्त 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित। * पत्रांक–1186, दिनांक–20.05.2016 के द्वारा अवर सचिव, सूचना एवं जन–संपर्क विभाग को पी0एम0आई0एस0 एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया। * प्रशासी विभाग के पत्रांक–287, दिनांक–23.03.2017 द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारियों को पूर्ण योजनाओं के हस्तांतरण के संबंध में पत्र दिया गया है। * जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, गया के पत्रांक–234, दिनांक–05.07.2017 द्वारा **गया** के लिए एन0ओ0सी0 प्राप्त हुआ। * *निगम के पत्रांक–2750, दिनांक–31.08.2017 द्वारा ₹4.96412 लाख का प्राक्कलन एवं फर्नीचर की विशिष्टियों सहित अनुमोदन हेतु पत्र भेजा गया, जिसके आलोक में प्रशासी विभाग के पत्रांक–1181, दिनांक–10.10.2017 द्वारा अनुमोदन का पत्र प्राप्त। परंतु वास्तुविदीय नक्शे तथा फर्नीचर की विशिष्टियों की पृष्ठवार अनुमोदित प्रति प्राप्त नहीं होने के कारण निगम द्वारा इस संबंध में निगम के पत्रांक–3181, दिनांक–18.10.2017 द्वारा पुनः पत्र भेजा गया है तथा पृष्ठवार अनुमोदन हेतु आग्रह किया गया था। उक्त के कम में प्रशासी विभाग के पत्रांक–1484, दिनांक–14.11.2017 द्वारा अनुमोदन प्राप्त। अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।*